

बाहर तैनात करने पर विचार नहीं किया गया। यह स्थानान्तरण नीति के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

कनिष्ठ इंजीनियरों (विधुत) को जो 1996 के दौरान स्थानान्तरित होने अपेक्षित थे, पहले ही बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

General Pool Accommodation to Delhi Police Personnel

3630. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Head Constables, Assistant Sub-Inspectors, etc. of the Delhi Police are eligible for General Pool accommodation;

(b) if not, whether any personnel of Delhi Police are in occupation of the General Pool accommodation; and

(c) if so, what are the reasons for continuing allotment to such personnel?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) No, Sir.

(b) and (c) Only gazetted staff of Delhi Police are eligible for accommodation from general pool as per Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963 as Delhi Police have their own pool of accommodation and Police colonies for non-gazetted staff.

बिहार में छोटे व मझौले शहरों के समन्वित विकास कार्यक्रम (आई. डी. एस. एम. टी.) का क्रियान्वयन

3631. श्री राजनाथ सिंह "सूर्य": क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में छोटे व मझौले शहरों के समन्वित विकास (आई. डी. एस. एम. टी.) के अन्तर्गत कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रमों में किन किन शहरों को शामिल किया गया है और जिलावर ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नालन्दा को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और नालन्दा की इस कार्यक्रम में शामिल में किये जाने वाले प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलु): (क) जी, हां।

(ख) अब तक आई. डी. एस. एम. टी. में शामिल बिहार के 40 शहरों की जिलावार सूची विवरण के रूप में संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) जी, नहीं।

(घ) आई. डी. एस. एम. टी. स्कीम में शामिल करने के लिए प्राथमिकता वाले शहरों की पहचान और चयन राज्य सरकारों द्वारा स्कीम के दिशानिर्देशों के तहत किया जाता है बिहार सरकार ने नालन्दा को निर्धारित प्राथमिकता वाले शहरों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

विवरण

आई. डी. एस. एम. टी. योजना में शामिल किए गए शहरों की सूची

(1979-80 के 31 मार्च, 1997 तक)

क्रम सं. राज्य/शहर	जिला
1. आरा	भोजपुर
2. वेगूसराय	बेगूसराय
3. बतिया	पश्चिम चम्परायन
4. चईवासा	सिंहभूम
5. छपरा	सारन
6. डालटनगंज	पालमु
7. देवगढ़	देवगढ़
8. धनबाद	धनबाद
9. दुमका	दुमका
10. गिरडीह	गिरडीह
11. गोपाल गंज	गोपालगंज
12. हाजीपुर	वैशाल

क्रम सं. राज्य/शहरजिला

13. हजारी बाग	हजारी बाग
14. कटिहार	कटिहार
15. सहरसा	सहरसा
16. बिहारशरीफ	नालन्दा
17. बोधगया	गया
18. बक्सर	भोजपुर
19. दरभंगा	दरभंगा
20. किशनगंज	किशनगंज
21. मधुबनी	मधुबनी
22. नवादा	नवादा
23. पुरनिया	पुरनिया
24. सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
25. शिवानी	शिवानी
26. जहानाबाद	जहानाबाद
27. शाहीगंज	साहिब गंज
28. यंका	भागलपुर
29. गढ़वा	पालमु
30. मुंगेर	मुंगेर
31. भागलपुर	भागलपुर
32. छत्रा	हजारीबाग
33. गौंडा	गौंडा
34. गुजफरपुर	मुजफ्फरपुर
35. राजगीर	नालन्दा
36. फारविसगंज	अररिया
37. गया	गया
38. लोहारडागा	लोहारडागा
39. शिहोहर	सीतामढ़ी
40. सुपौल	सहरसा

**Unauthorised Construction/Alterations,
and Subletting of Government Quarters**

3632. DR. B.B. DUTTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any investigations have been made by Government to check unauthorised construction/alterations and subletting of Government Quarters in Delhi;

(b) if so, the details thereof, locality-wise ;

(c) the action taken/proposed to be taken against the persons found guilty; and

(d) the steps taken by Government to stop such activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) to (d) On receipt of a report of unauthorised construction/alterations, a show cause notice is issued to the concerned allottee for the removal of the said unauthorised construction/alterations within the stipulated period, and if the allottee fails to remove the unauthorised construction within the stipulated period, the allotment of accommodation is cancelled as per the provisions of the Allotment Rules and eviction proceedings initiated under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971.

As regards subletting of General Pool Residential Accommodation, 4488 cases of suspected subletting were detected as a result of door to door survey carried out in pursuance of Supreme Court directions and show cause notices were served on these allottees. Thereafter, upto September, 1996, 1085 General Pool Residential Accommodation has been cancelled and 634 got vacated/evicted.

**Investment by HUDCO on Infrastructure
Sector**

3633. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) is:-